डिजीटल पत्र

दैनिक

कांग्रेस दर्पण

पटना, 28 जून, शुक्रवार, 2024

बिहार प्रदेश कांग्रेस सेवादल सदाकत आश्रम पटना-10

18वीं लोकसभा के पहले सत्र के दौरान आपातकाल की चर्चा पर भड़की कांग्रेस, बिरला से मिले राहुल गांधी

संवाददाता । कांग्रेस दर्पण

नई दिल्ली

18वीं लोकसभा के पहले सत्र के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आपातकाल का जिक्र कर उसे काला दिवस बताया। अब इस मामले पर कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। इसी संदर्भ में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने ओम बिरला से मुलाकात की।

इमरजेंसी के जिक्र से बचा जाना चाहिए था: कांग्रेस

राहुल गांधी ने सदन में अध्यक्ष द्वारा आपातकाल के जिक्र को स्पष्ट रूप से राजनीतिक करार दिया। उन्होंने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष को इससे बचना चाहिए था। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष के साथ हुई बैठक के बाद पत्रकारों को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लोकसभा स्पीकर के साथ मुलाकात एक शिष्टाचार भेंट थी। इस दौरान अध्यक्ष ओम बिरला ने राहुल गांधी को विपक्ष का नेता घोषित किया।

बैठक के बाद क्या बोले वेणुगोपाल?

केसी वेणुगोपाल से जब इस बारे में पूछा गया कि क्या लोकसभा अध्यक्ष के साथ हुई मुलाकात के दौरान राहुल गांधी ने सदन में उठे इमरजेंसी के मुद्दे का जिक्र किया, जिस पर उन्होंने कहा कि हमने संसद के कामकाज सहित अन्य कई मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान यह भी मुद्दा उठा। उन्होंने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष से इंडी गठबंधन के कई नेताओं ने भी मुलाकात की।

राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष से क्या कहा?

उन्होंने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी ने आपातकाल के बारे में अध्यक्ष को जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि सदन में आपातकाल का जिक्र करना स्पष्ट रूप से एक राजनीतिक है और इसे टाला जा सकता था। वहीं, बैठक के बाद भी कांग्रेस लगातार इस मुद्दे पर विरोध कर रही है।

वेणुगोपाल ने लोकसभा अध्यक्ष को लिखा पत्र

वेणुगोपाल ने भी इस मसले पर ओम बिरला को पत्र लिखा। उन्होंने इस दौरान पदभार ग्रहण करने के बाद अपने पहले कार्य के रूप में आपातकाल पर प्रस्ताव लाने पर कांग्रेस की ओर से नाराजगी जताई। पत्र में उन्होंने कहा कि 26 जून को सदन में जो भी कुछ हुआ वह बहुत ही चौंकाने वाला है। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष द्वारा आपातकाल के जिक्र को राजनीति से प्रेरित बताया।

कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह बोले , भाजपा सरकार में प्रतियोगी परीक्षाएं व सरकारी भर्ती बनी व्यवसाय

संवाददाता । कांग्रेस दर्पण

नई दिल्ली । मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस से राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने भाजपा सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगाया है। संगम नगरी में राष्ट्रीय सुरक्षा कर्मचारी महासंघ की बैठक में शामिल होने आए दिग्विजय सिंह ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार में प्रतियोगी परीक्षाएं और सरकारी भर्ती व्यवसाय बन चुकी है। यह हजारों करोड़ रुपये का कारोबार है।

उन्होंने कहा कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। नीट के मामले में प्रधानमंत्री मोदी चुप्पी साधकर बैठे हैं। दस वर्ष में 41 बार परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा की डबल इंजन सरकार में प्रतियोगी परीक्षाएं और सरकारी भर्ती व्यवसाय बन चुकी है। यह हजारों करोड़ रुपये का कारोबार है। निरंतर गड़बड़ी चल रही है, इस पर कोई अंकुश नहीं है।

दिग्विजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर कभी नहीं बोलते। उन्होंने बीते दस वर्ष में सिर्फ झूठ बोला और नफरत फैलाई। प्रधानमंत्री मोदी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अतीत को कुरेदते रहे। कांग्रेस को कोसने के सिवाए कुछ भी नहीं किया। कांग्रेस नेता ने एनडीए की केंद्र सरकार के भी शीघ्र गिर जाने का भी दावा किया। उन्होंने कहा कि अब हालात कितने खराब है इससे अनुमान लगाएं कि अयोध्या के राम मंदिर की छत भी लीक हो रही। आमजन को सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। प्रधानमंत्री को धरातल पर देखना होगा। जन आकांक्षाओं को समझना होगा। उसके अनुरूप ठोस कदम भी उठाने होंगे।

देश के उच्च सदन, राज्यसभा में सांसद सदस्य के रूप में पुनः शपथ ग्रहण किया

संवाददाता । कांग्रेस दर्पण

देश के उच्च सदन, राज्यसभा में सांसद सदस्य के रूप में पुनः शपथ ग्रहण किया। मैं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री Mallikarjun Kharge जी, उढढ चेयरपर्सन माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री Rahul Gandhi जी और पार्टी के शीर्ष नेताओं एवं इंडिया गठबंधन बिहार के सभी विधायकगण के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ।

मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस महत्वपूर्ण संवैधानिक कर्तव्य के निर्वहन और संविधान की रक्षा के लिए सदैव पूरी निष्ठा से प्रयासरत रहूँगा।

नीट पेपर लीक मामले में संसद का घेराव करेगी झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस कमिटी- गुंजन सिंह

संवाददाता । कांग्रेस दर्पण

रांची

झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस कमिटी की अध्यक्ष गुंजन सिंह की अध्यक्षता में आज हुई बैठक में कहा गया नीट पेपर लीक मामले में संसद का घेराव किया जायेगा। वहीं, बैठक में लोकसभा चुनाव-2024 के चुनाव परिणाम पर समीक्षा भी की गई।

आगामी विधानसभा चुनाव की कार्य योजना पर रणनीति बनाई गई। साथ ही संगठन की मजबूती पर विस्तारपूर्वक चर्चा हुई। अध्यक्ष गुंजन सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव परिणाम हमारे अपेक्षा अनुरूप नहीं रहा है। और बेहतर करने की जरूरत थी। आगामी विधानसभा चुनाव-2024 बहुत ही करीब आ गया है, जिसे जो भी जिम्मेदारी दी गई है, मुस्तैदी के साथ अपने अपने जिला और क्षेत्र में जुट जाएं। बैठक में प्रदेश पदाधिकारियों एवं जिला अध्यक्षों ने शिरकत की।

कार्यक्रमों की जानकारी दी

प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने दिल्ली में संपन्न बैठक में मिली एक्शन प्लान की जानकारी देते हुए कहा कि आगामी अगस्त माह में राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक होगी।

जिसमें महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा, झारखंड प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर शामिल होंगे। प्रखंड महिला कांग्रेस अध्यक्षों का 3 दिनों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होगा। सभी जिलों में नारी न्याय सम्मेलन एवं जिला स्तर से लेकर बूथ तक पदयात्रा किया जाएगा। पार्टी मैनिफेस्टो को जन जन तक पहुंचाना है, महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए हेल्थ कैम्प लगाया जायेगा। नीट पेपर लीक मामले और महिला आरक्षण पर संसद घेराव कार्यक्रम होगा। इसके साथ ही बढ़ती महंगाई, टोलटैक्स, भारतीय रुपया में गिरावट, मुहल्ला पदयात्रा एवं मेरा बूथ मेरी ज़िम्मेवारी पर विशेष रूप से महिला कांग्रेस कार्यक्रम चलायेगा।

मौके पर ये लोग थे मौजूद

बैठक में प्रदेश महासचिव पिंकी सिंह, संगीता टोप्पो, प्रीति सहाय, पुनीता चौधरी, सुन्दरी तिर्की, अनीता सिन्हा, शांति बाला केरकेटा, वर्षा, अमृता भगत, सीता राणा, अजन्ता सामद, दिव्या मिंज, ग्रेसी मिंज, नीतू देवी, हेमन्ती जायसवाल, रूबी खातून, नमिता बा, मनिषा तिर्की, प्रभा तिग्गा आदि महिलाएं शामिल थीं।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने लगाया आरोप - राष्ट्रपति से झूठ बुलवाकर अपनी वाहवाही करवा रहे PM मोदी

संवाददाता । कांग्रेस दर्पण

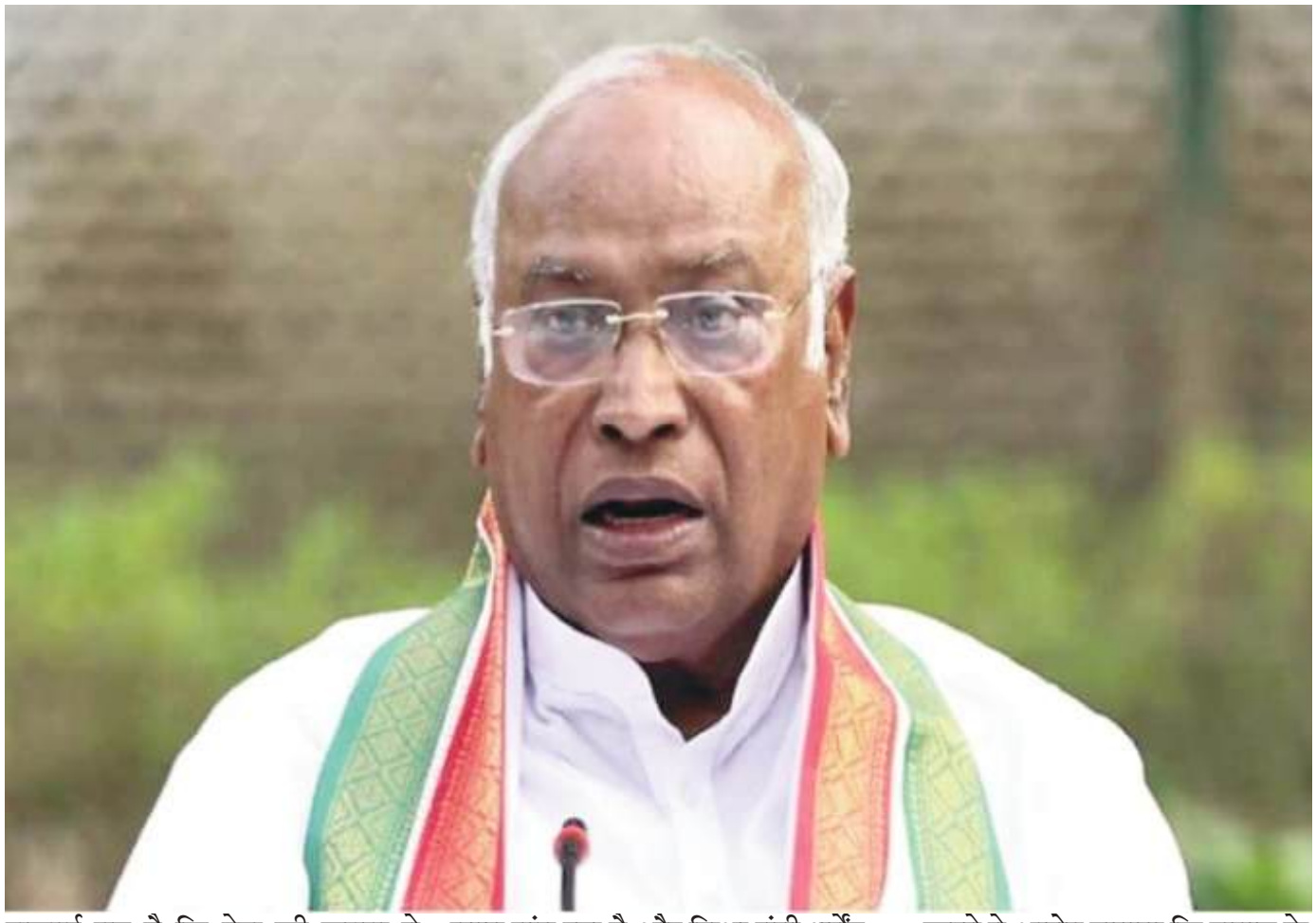

नई दिल्ली

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि राष्ट्रपति के, ''मोदी सरकार लिखित'' अभिभाषण को सुनकर ऐसा लगा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 2024 के लोकसभा चुनाव के जनादेश को नकारने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने यह दावा भी किया कि प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति से 'झूठ बुलवाकर' अपनी वाहवाही करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि देश की जनता उन्हें नकार चुकी है। खरगे ने यह भी कहा कि अभिभाषण में महंगाई, बेरोजगारी, मणिपुर में हिंसा और जम्मू-कश्मीर में आतंकी हमलों जैसे प्रमुख मुद्दों का उल्लेख नहीं था।

जनता ने "400 पार" के उनके नारे को ठुकरा दिया

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अठारहवीं लोकसभा में पहली बार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बृहस्पतिवार को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दुनिया देख रही है कि भारत के लोगों ने लगातार तीसरी बार स्थिर और स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई है और छह दशक बाद ऐसा हुआ है। खरगे ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''राष्ट्रपति के, मोदी सरकार द्वारा लिखित अभिभाषण को सुनकर ऐसा लगा जैसे मोदी जी जनादेश को नकारने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। जनादेश उनके ख़िलाफ़ था, क्योंकि देश की जनता ने ''400 पार'' के उनके नारे को ठुकरा दिया और भाजपा को 272 के आंकड़े से दूर रखा। मोदी जी इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। वह ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे कुछ बदला ही नहीं, जबकि सच्चाई यह है कि देश की जनता ने बदलाव मांगा था।"

66 भर्ती परीक्षाओं में 12 में पेपर लीक और धांधली

उन्होंने कहा, ''मैं राज्यसभा में अपने भाषण में विस्तृत प्रतिक्रिया दूंगा, पर प्रथमदृष्टया मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। नीट घोटाले में लीपापोती नहीं चलेगी।" कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया, ''पिछले पांच वर्षों में एनटीए द्वारा कराई गईं 66 भर्ती परीक्षाओं में कम से कम 12 में पेपर लीक और धांधली हुई है, जिससे 75 लाख से अधिक युवा प्रभावित हुए हैं। मोदी सरकार केवल यह कहकर कि ₹दलगत राजनीति से ऊपर उठना चाहिए₹, अपनी जवाबदेही से भाग नहीं सकती।" उन्होंने कहा कि युवा न्याय मांग रहा है और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इसकी ज़िम्मेदारी लेनी होगी। खरगे ने कहा, ''देश का हर दूसरा युवा बेरोज़गार है और भाषण में बेरोज़गारी दूर करने की कोई ठोस नीति सामने नहीं आई है। सिर्फ़ बातें करने से समस्या का हल नहीं निकलता, इसके लिए निर्णायक कदम उठाने होते हैं।" उन्होंने कहा कि देश के समक्ष खड़े पांच प्रमुख मुद्दों- कमरतोड़ महँगाई, मणिपुर की हिंसा, रेल दुर्घटना एवं यात्री ट्रेनों की दुर्दशा, जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी हमले और दलितों, आदिवासियों व अल्पसंख्यकों पर भाजपा शासित राज्यों में बढ़ते अत्याचार को लेकर अभिभाषण में कुछ नहीं कहा गया।

BJP एवं RSS की सोच केवल समाज को बांटने की

खरगे ने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान नरेन्द्र मोदी जी के भाषणों ने इस तथ्य पर कई बार मोहर लगाई कि भाजपा एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सोच केवल समाज को बांटने की है। उन्होंने दावा किया, '' ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, असम व उत्तर प्रदेश जैसे भाजपा शासित राज्यों में मोदी सरकार के आते ही मॉब लिंचिंग, भीड़तंत्र, सांप्रदायिक हिंसा और ग़रीबों के घरों पर ग़ैरकानूनी तरीके से बुलडोज़र चलाए जाने की घटनाएं बढ़ी हैं। पर सत्ताधारी दल पूरी तरह मौन धारण किए हुए है।" कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया, ''कुल मिलाकर, मोदी जी, महामहिम राष्ट्रपति जी से झूठ बुलवाकर, वाहवाही लूटने का ओछा प्रयास कर रहे हैं, जबकि उन्हें 2024 के चुनाव में भारत की जनता नकार चुकी है।"

शपथ लेने के दौरान शशि थरूर ने जय संविधान कहा - इस मामले को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा का बयान सामने आया

संवाददाता । कांग्रेस दर्पण

नई दिल्ली

लोकसभा में सांसद पद की शपथ लेने के दौरान शशि थरूर ने जय संविधान कहा, जिसके बाद स्पीकर ने उन्हें टोक दिया। दीपेन्द्र हुड्डा ने जब इसका विरोध किया तो स्पीकर ने उन्हें भी सख्ती से चुप करा दिया। इस पूरे मामले पर अब प्रियंका गांधी वाड्रा का बयान सामने आया है।

प्रियंका गांधी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, ₹क्या भारत की संसद में 'जय संविधान' नहीं बोला जा सकता? संसद में सत्ता पक्ष के लोगों को असंसदीय और असंवैधानिक नारे लगाने से नहीं रोका गया, लेकिन विपक्षी सांसद के 'जय संविधान' बोलने पर आपत्ति जताई गई। चुनाव के दौरान सामने आया संविधान विरोध अब नये रूप में सामने आया है जो हमारे संविधान को कमजोर करना चाहता है।₹

उन्होंने आगे लिखा कि जिस संविधान से संसद चलती है, जिस संविधान की हर सदस्य शपथ लेता है, जिस संविधान से हर नागरिक को जान और जीवन की सुरक्षा मिलती है, क्या अब विपक्ष की आवाज दबाने के लिए उसी संविधान का विरोध किया जाएगा?

आपको बताते चलें, संसद सत्र के चौथे दिन शशि थरूर ने लोकसभा में सांसद पद की शपथ ली। शपथ के बाद उन्होंने 'जय संविधान' के नारे लगाए, जिसको लेकर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि आप संविधान की शपथ तो ले ही रहे हैं, तो इसे बोलने की क्या जरूरत है। इसके बाद कांग्रेस के कई नेता ओम बिरला के खिलाफ खड़े होकर विरोध जताने लगे।

कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने स्पीकर से कहा कि इस पर आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसके बाद दीपेंद्र हुड्डा को जवाब देते हुए स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि किस पर आपत्ति हो, किस पर न हो, इसकी सलाह मत दिया करो, चलो बैठो।

नीट पेपर लीक केस : NSUI के छात्र घुसे NTA के दफ्तर में, झड़प के बाद कार्यालय में जड़ा ताला

संवाददाता । कांग्रेस दर्पण

नीट पेपर लीक मामले में आज NSUI के छात्र विरोध प्रदर्शन करते हए दिल्ली स्थित NTA के दफ्तर में घुस आये। इस दौरान दफ्तर में तैनात सुरक्षा कर्मियों की छात्रों से झड़प हुई। झड़प के बीच ही ठरवकके सदस्यों ने ठळअ दफ्तर में ताला जड़ दिया। मिली खबर के मुताबिक इस प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में छात्र आज दिल्ली की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन के लिए निकले हैं। इनकी अगुवाई कांग्रेस की छात्र विंग NSUI कर रही है।

पेपर लीक मामले में आज 2 गिरफ्तारियां

इधर, नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने आज पहली गिरफ्तारी की है। सीबीआई की टीम ने मामले में कार्रवाई करते हुए पटना से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार युवकों के नाम आशुतोष और मनीष हैं। जांच एजेंसी सूत्रों ने बताया कि इसी मनीष प्रकाश ने पटना के लर्न एंड प्ले स्कूल में कमरा बुक करवाया था। जानकारी हो कि इसी कमरे में छात्रों के आंसर रटवाया गया था। सीबीआई ने मनीष प्रकाश को पूछताछ के लिए बुलाया था, जहां उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

सीबीआई ने किया है केस टेकओवर

बता दें कि इस केस की जांच पहले बिहार की आर्थिक अपराध इकाई की टीम कर रही थी। उइकने बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई (EOU) से 26 जून को यह केस अपने हाथ में लिया था। अब तक 5 राज्यों में पुलिस ने 27 से ज्यादा गिरफ्तारियां की हैं। सीबीआई की टीम झारखंड के हजारीबाग में भी कई लोगों से पूछताछ करने बीते बुधवार को पहुंची थी। गुरुवार को भी पूछताछ जारी रही। झारखंड के हजारीबाग के ओएसिस स्कूल से पेपर लीक के कनेक्शन मिले हैं। शक है कि यहीं से नीट का पेपर लीक हुआ है। इस कांड का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया अभी फरार है।

सांसद आरके चौधरी ने सेंगोल को राजशाही का प्रतीक बताते हुए हटाने की मांग कर दी, डीएमके ने भी कहा हटाने को

संवाददाता ।कांग्रेस दर्पण

नई दिल्ली
समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद आरके चौधरी ने संसद भवन में लगे सेंगोल को राजशाही का प्रतीक बताते हुए हटाने की मांग कर दी थी। इसके बाद से ही विवाद जारी है। एक पक्ष ने उनकी मांग को सही ठहराया तो वहीं भाजपा समेत एनडीए के नेताओं ने इसे भारतीय संस्कृति का अपमान करने वाला बताया है। भाजपा ने तो इस मामले में तमिलनाडु की पार्टी डीएमके का भी जवाब मांगा, जो वहां राज्य की सत्ता में है। उसने कहा कि डीएमके को बताना चाहिए कि क्या उसके साथ गठबंधन में शामिल दल की ऐसी मांग ठीक है, जो तमिल संस्कृति का अपमान करने वाली है। दरअसल सेंगोल को तमिलनाडु से ही लाया गया था।

ऐसे में भाजपा को लग रहा था कि वह इसके जरिए डीएमके समेत कठउक्रअ अलायंस को घेर लेगी। लेकिन अब डीएमके ने भी कह दिया है कि सेंगोल को हटा देना चाहिए। डीएमके नेता टीकेएस एलानगोवन ने कहा, 'जैसा कि सपा सांसद आरके चौधरी ने कहा कि सेंगोल राजशाही का प्रतीक है। इसे राजा लोग इस्तेमाल करते थे। एक लोकतांत्रिक देश में इसकी कोई जरूरत नहीं है। यह ब्रिटिश शासकों द्वारा जवाहरलाल नेहरू को उपहार के तौर पर दिया गया था। इसकी सही जगह संग्रहालय में ही है। हमारी इस पर कोई राय नहीं है। लेकिन हम समझते हैं कि यदि समाजवादी पार्टी ने ऐसी मांग रखी है तो यह सही ही है।'

सपा सांसद आरके चौधरी ने लोकसभा स्पीकर से उठाई थी क्या मांग

यूपी की मोहनलालगंज लोकसभा सीट से सांसद आरके चौधरी ने लोकसभा स्पीकर को लिखे पत्र में सेंगोल को हटाने की मांग की थी। चौधरी ने कहा था, 'मैं जब शपथ ले रहा था तो वहीं पर सेंगोल लगा देखा। इसका सेंगोल का अर्थ राजदंड से है। राजदंड का मतलब होता है, राजा का दंड। अब जब देश में लोकतंत्र है और व्यवस्था संविधान के अनुसार चल रही है तो फिर इसकी हमें क्या जरूरत है। इसे सदन से हटा देना चाहिए। राजा-रजवाड़ों का शासन खत्म करके ही देश में लोकतंत्र लाया गया था। इसलिए अब इसकी हमें क्या जरूरत है। अब तो देश संविधान से ही चलना चाहिए।'

मीसा भारती भी बोलीं- मांग तो गलत नहीं की, हम भी साथ

इस पर विवाद बढ़ा तो पक्ष और विपक्ष में भी राजनीतिक दल बंट गए। आरके चौधरी का आरजेडी की नेता मीसा भारती ने भी समर्थन किया है। मीसा ने कहा कि जिसने भी यह मांग की है। मैं स्वागत करती हूं। वहीं भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि यह भारतीय संस्कृति का अपमान है। पूनावाला ने कहा, 'समाजवादी पार्टी ने इससे पहले रामचरितमानस का भी अपमान किया था। अब वह भारतीय संस्कृति से जुड़े सेंगोल का अपमान कर रही है। डीएमके को इस पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए कि वह सेंगोल के साथ है या उसका अपमान चाहती है।'

आगामी विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस नर्सिंग घोटाले को जोर-शोर से उठाएगी

संवाददाता । कांग्रेस दर्पण

भोपाल

1 जुलाई से प्रारंभ होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस नर्सिंग घोटाले को जोर-शोर से उठाएगी। स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से इस विषय पर चर्चा कराने की मांग पहले ही दिन कार्य मंत्रणा समिति में रखी जाएगी। सदन में उठाए जाने वाले मुद्दों को अंतिम रूप 30 जून को होने वाली विधायक दल की बैठक में दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव के बाद हो रहे विधानसभा के इस पहले सत्र में सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस के सभी विधायकों ने अलग-अलग माध्यमों से प्रश्न लगाए हैं।

19 दिन का होगा मानसून सत्र

विधानसभा सचिवालय को 19 दिवसीय सत्र के लिए 4500 से अधिक प्रश्न मिल चुके हैं। पार्टी विधायकों ने महिला, अनुसूचित जाति-जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग पर हुए अत्याचार की घटनाओं को लेकर अधिकतर प्रश्न पूछे हैं।

जीतू पटवारी का आरोप, भाजपा ने की वादाखिलाफी

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का कहना है कि भाजपा ने जनता से वादाखिलाफी की है। विधानसभा चुनाव में युवा, महिला, किसान समेत अन्य वर्गों से जो वादे किए गए थे, वे एक भी पूरे नहीं किए हैं और उस दिशा में कदम भी नहीं बढ़ाया।

किसानों को न ता गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपये प्रति क्विंटल लिया और न ही धान के 3,100 रुपये। लाड़ली बहना को 3000 रुपये प्रतिमाह देने का वादा किया था, लेकिन इसे भी पूरा नहीं किया। लाड़ली बहनों को आवास देने की बात हो या 60 प्रतिशत अंक पाने पर लैपटॉप देने की घोषणा, कोई भी पूरी नहीं हुई। इन सभी विषयों को विधानसभा में जोर शोर से उठाया जाएगा। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का कहना है कि 30 जून को विधायक दल की बैठक बुलाई है। इसमें तय किया जाएगा कि भाजपा सरकार की वादाखिलाफी, भ्रष्टाचार, नर्सिंग समेत अन्य घोटाले को सदन में किस मुद्दे को किस तरह उठाया जाएगा।

योजनाओं का कार्यान्वयन सबसे बड़ी जरूरत

संवाददाता । कांग्रेस दर्पण

बालू की कमी और महंगाई के कारण अबुआ आवास सहित सरकार की अनेक कल्याणकारी और विकास योजनायें प्रभावित तिर्की ने विश्वास व्यक्त किया कि सरकार जिस प्रकार से आमजन की जरूरतों एवं आकांक्षाओं के प्रति समर्पित है उसमें यह बात निश्चित है कि यह गंभीर समस्या मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के संज्ञान में होगी लेकिन फिर भी इस पर ध्यान देना बहुत अधिक आवश्यक है क्योंकि, तेज गति से सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन आज की सबसे बड़ी जरूरत है।

संसद में सेंगोल की जगह संविधान की प्रति लगाने में क्या दिक्कत: अखिलेश यादव

संवाददाता । कांग्रेस दर्पण

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने अपने सांसद आरके. चौधरी द्वारा लोकसभा से सेंगोल हटाकर उसकी जगह संविधान की विशालकाय प्रति स्थापित करने को लेकर लोकसभा स्पीकर को लिखे गए पत्र का समर्थन करते हुए कहा है कि आखिर सरकार को सेंगोल की जगह संविधान की प्रति लगाने में क्या दिक्कत है।

हालांकि, संसद भवन परिसर में मीडिया से बात करते हुए सपा सांसद आरके. चौधरी ने कहा कि उन्हें जब लोकसभा में राजदंड और राजतंत्र का प्रतीक सेंगोल नजर आया तो उन्होंने इसे हटाने के लिए तुरंत पत्र लिख दिया क्योंकि लोकतंत्र में इसका कोई स्थान

नहीं है।

एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पत्र लिखने से पहले उनकी पार्टी अध्यक्ष Akhilesh Yadav से कोई बात नहीं हुई थी, पत्र के चर्चा में आने के बाद आज उनकी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात हुई है। उन्होंने कहा कि वह अपनी मांग को लेकर सहयोगी दलों से भी बात करेंगे।

इससे पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि यह सरकार का भाषण था और सरकार जब यह दावा करती है कि हम दुनिया की पांचवी अर्थव्यवस्था बन गए हैं और तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएंगे तो फिर देश का किसान क्यों दुखी है?

बड़े पैमाने पर नौजवान बेरोजगार क्यों हैं? अग्निवीर जैसी आधी-अधूरी योजना सरकार को क्यों लागू करनी पड़ रही है? देश में महंगाई क्यों है?

राष्ट्रपति के अभिभाषण में आपातकाल का जिक्र होने पर प्रतिक्रिया देते हुए Akhilesh Yadav ने कहा कि जहां तक आपातकाल का मसला है, यह सवाल भाजपा के लोगों से पूछना चाहिए कि आपातकाल में जो लोग जेल में गए थे, भाजपा ने उन लोगों के लिए क्या किया?

उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी (SP) की सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल में रहने वाले लोगों को मानदेय दिया और कई तरह की सुविधाएं भी दी।

ठएएळ और अन्य परीक्षाओं पर दोनों सदनों में विस्तृत चर्चा चाहता है विपक्ष, लाएगा स्थगन प्रस्ताव

संवाददाता । कांग्रेस दर्पण

हाल में हुई NEET परीक्षा में Paper leak मामले पर विपक्ष गंभीर है। नीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विपक्ष संसद के दोनों सदनों में खास चर्चा चाहता है। इसके लिए विपक्ष संसद में स्थगन प्रस्ताव लाएगा। विपक्ष ने कहा है कि वह कल संसद में इस मुद्दे को उठाएगा। वहीं बताया जा रहा है कि सरकार भी इस मामले पर सवालों के जवाब देने के लिए तैयार है।

नीट के मुद्दे पर विपक्ष के रुख की बात करें तो कांग्रेस ने हाल ही में राष्ट्रपति Draupadi Murmu के

अभिभाषण पर भी सवाल उठाया।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के अभिभाषण में देश की जनता की समस्याओं को नजरअंदाज किया गया है और जनहित के मुद्दों का कहीं जिक्र नहीं हुआ है, तथा उन पर पूरी तरह से पर्दा डालने का काम हुआ है। खरगे ने कहा, ''मैं राज्यसभा में अपने भाषण में विस्तृत प्रतिक्रिया दूंगा, पर प्रथमदृष्टया मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं।''

संसद में स्थगन प्रस्ताव किसी सार्वजनिक महत्व के मामले की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए पेश किया जाता है। इसे स्वीकार करने के लिए 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है।

इसे संसदीय कार्यवाही के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक कहा जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो स्थगन प्रस्ताव एक असाधारण प्रक्रिया है, जिसे स्वीकार किए जाने पर सदन के सामान्य कामकाज को स्थगित करके तत्काल सार्वजनिक महत्व के किसी निश्चित मामले पर चर्चा की जाती है।

BJP से बड़प्पन की उम्मीद करना बेमानी है और नरेंद्र मोदी से बड़ा दिल दिखाने की अपेक्षा करना बेवक़ूफ़ी

संवाददाता । कांग्रेस दर्पण

BJP से बड़प्पन की उम्मीद करना बेमानी है और नरेंद्र मोदी से बड़ा दिल दिखाने की अपेक्षा करना बेवक़ूफ़ी.

संसद सत्र शुरू हुआ, नेता विपक्ष राहुल गांधी और नेता सदन नरेंद्र मोदी एक साथ स्पीकर महोदय को लेकर ऊपर पहुँचे.

एक नई शुरुआत की पहल ख़ुद राहुल गांधी ने पहले हाथ बढ़ा कर की. नेता प्रतिपक्ष के रूप में सदन में उनका पहला वक्तव्य बेहद उम्दा था. धीर गंभीर बात, हिंदुस्तान के लोगों के प्रतिनिधित्व की बात करते हुए - विपक्ष की आवाज़ को जगह दिये जाने की पुरज़ोर पैरवी की. यहाँ से अगर BJP चाहती तो एक अच्छी पहल हो सकती थी.

लेकिन छोटे मन के लोगों से बड़ी बातों की उम्मीद करना ही ग़लत है.

स्पीकर ने 49 साल पहले लगी इमरजेंसी का प्रस्ताव रखा, फिर आज 27 जून को राष्ट्रपति ने सरकार द्वारा लिखित अभिभाषण में भी 25 जून 1975 की इमरजेंसी का ज़िक्र किया.

पुराने घाव कुरेदने से क्या हासिल होगा? इमरजेंसी का निर्णय ग़लत था, इसमें कोई दोराय नहीं है. लेकिन यह भी सच है कि इंदिरा जी ने ख़ुद उस गलती को माना था और लोकतांत्रिक चुनाव कराए थे. यही नहीं, इमरजेंसी से कोई वास्ता ना होने के बावजूद स्वयं राहुल गांधी ने इमरजेंसी को एक गलती बताया है और ऐसा कभी दोबारा ना हो इसीलिए वह संविधान को हर हाल में सुरक्षित रखने के किए प्रतिबद्ध हैं.

लेकिन अब छेड़ ही दिया है तो कुछ सवाल पूछ ही लिए जाएं-

1) एक साथ एक ही सत्र में क़रीब 146 विपक्षी सांसदों को लोक सभा से निलंबित करना, क्या यह इमरजेंसी नहीं है?

2) विपक्षी सांसदों के माइक बंद कर देना, क्या यह एमरजेंसी नहीं है?

3) राहुल गांधी के 14 मिनट के भाषण में 11 मिनट ओम बिरला की शक्ल दिखाना, क्या यह इमरजेंसी नहीं है?

4) 51 मिनट के राष्ट्रपति के आज के अभिभाषण में 6 बार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को और 73 बार नरेंद्र मोदी को दिखाना, क्या ये इमरजेंसी नहीं है?

5) स्पीकर का 'जय संविधान' बोलने पर आपत्ति करना, क्या यह इमरजेंसी नहीं है?

6) जबरन काले कृषि क़ानून, उअअ, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, भारतीय न्याय संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 पास कराना, क्या यह इमरजेंसी नहीं है?

7) सिर्फ़ वॉइस वोट से क़ानून को पारित कराना, लोकसभा में 35% विधेयक एक घंटे से कम समय में पारित कराना और मात्र 16% बिल को Parliamentary Standing Committee के भेजना, क्या यह इमरजेंसी नहीं है?

8) संसद के प्रांगण से छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा गाँधी और बाबासाहेब की प्रतिमाओं को बिना विपक्ष से चर्चा किये बियाबान में डाल देना, क्या यह इमरजेंसी नहीं है?

9) विधायकों की नीलामी करके चुनी हुई सरकारें गिराना, क्या यह इमरजेंसी नहीं है?

10) विपक्ष को ED, CBI, Income Tax से प्रताड़ित करना, क्या यह इमरजेंसी नहीं है?

11) चुनाव के दौरान मुख्यमंत्रियों को जेल में डालना, मुख्य विपक्षी पार्टी के बैंक खाते बंद करना, क्या यह इमरजेंसी नहीं है?

11) विपक्षी नेताओं की, न्यायाधीशों की, अफ़सरों की, अपने ख़ुद के मंत्रियों की पेगसस से जासूसी करना, क्या यह इमरजेंसी नहीं है?

12) एक साल से जलते हुए मणिपुर को उसके हाल पर छोड़ देना, क्या यह इमरजेंसी नहीं है?

13) चीनी अतिक्रमण से आक्रोशित लद्दाख की अनदेखी करना, क्या यह इमरजेंसी नहीं है?

14) किसानों को सवा साल तक दिल्ली की सरहद पर छोड़ देना जिसमें 750 किसानों की शहादत हो गई, क्या यह इमरजेंसी नहीं है?

15) किसान नरसंहार के मुख्य अभियुक्त के पिता को गृह राज्यमंत्री बनाए रखना, क्या यह इमरजेंसी नहीं है?

16) रोज़गार की माँग करते युवाओं को पुलिस से बर्बर लाठीचार्ज कराना, क्या यह इमरजेंसी नहीं है?

17) छात्रों को प्रदर्शन करने पर जेल में डाल देना, क्या यह इमरजेंसी नहीं है?

18) पेपर पर पेपर लीक होना, परीक्षाएँ स्थगित होना, क्या यह इमरजेंसी नहीं है?

19) 21 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट को गिरफ़्तार करना, क्या यह इमरजेंसी नहीं है?

20) पत्रकारों पर असहज सच दिखाने के लिए राष्ट्रद्रोह के मुक़दमे लगाना, क्या यह इमरजेंसी नहीं है?

21) मीडिया को अपने बस में करने के बाद सोशल मीडिया और यूट्यूब पर शिकंजा कसने की कोशिश करना, क्या यह इमरजेंसी नहीं है?

22) सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ की सबसे बड़ी फैक्ट्री चलाने के बाद अगर किसी और का पोस्ट ठीक ना लगे तो उसे सीधे जेल में डाल देना, क्या यह इमरजेंसी नहीं है?

23) मनमाने फ़रमानों से लॉकडाउन लगाना, नोटबंदी करना, क्या यह इमरजेंसी नहीं है?

24) औरतों के ख़िलाफ़ जघन्य से जघन्य अपराध हों और सरकार हर बार आरोपी को संरक्षण दे, क्या यह इमरजेंसी नहीं है?

: Supriya Shrinate जी